

मुकदमों का विवरण

बालविंदर सिंह (बिंदा) बनाम।

नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (2014 की आपराधिक अपील संख्या 1136) 22 सितंबर, 2023

[बी. आर. गवई, हिमा कोहली और प्रशांत कुमार मिश्रा, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:मामला नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए इकबालिया बयान के साक्ष्य में स्वीकार्यता से संबंधित है।⁶⁷ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985; और अभियोजन पक्ष द्वारा उचित संदेह से परे निषिद्ध पदार्थ के कब्जे को साबित करना।

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, **1985** -धारा **67**-अभियुक्त यू/एस द्वारा दिया गया इकबालिया बयान।**67** मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के एक अधिकारी के समक्ष-साक्ष्य में स्वीकार्यता:

आयोजित किया गया:अभियुक्त द्वारा दिया गया बयान और यू/एस दर्ज किया गया।⁶⁷ एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अंतर्गत एक अपराध के मुकदमे में एक इकबालिया बयान के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है-किसी भी आरोपी द्वारा एक अधिकारी को दिया गया कोई भी इकबालिया बयान जिसे यू/एस शक्तियों के साथ निवेश किया गया है।⁵³ एन. डी. पी. एस. अधिनियम, इस कारण से वर्जित है कि इस तरह के अधिकारी एस के अर्थ में "पुलिस अधिकारी" हैं।²⁵ साक्ष्य अधिनियम-साक्ष्य अधिनियम, 1872 -एस. 25.[पैरा 10]

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, **1985** -धारा **54**-अवैध वस्तुओं के कब्जे से अनुमान-"उचित संदेह से परे प्रमाण बनाम" संभावना की प्रधानता ":

आयोजित किया गया:अभियोजन पक्ष पर प्रारंभिक भार उन आवश्यक कारकों को स्थापित करने के लिए डाला जाता है जिन पर उसका मामला आधारित है-अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त बोझ को निर्वहन करने के बाद, अपनी बेगुनाही साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी पर आ जाती है-हालाँकि, आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए आवश्यक सबूत का मानक 101 नहीं है।

बालविंदर सिंह (बिंदा) बनाम नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरियो 102

अभियोजन पक्ष से अपेक्षा के अनुसार उच्च-एस के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए।
54, अभियोजन पक्ष के लिए यह आवश्यक है कि वह अभियुक्त द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ रखने के तत्व को स्थापित करे ताकि आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बोझ

स्थानांतरित किया जा सके-प्रतिबंधित पदार्थ रखने के इस पहलू को अभियोजन पक्ष द्वारा उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए।[पैरा 15 और 16]

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेन्स एक्ट, **1985।67** और **54-हेरोइन** की वाणिज्यिक मात्रा रखने के लिए दो व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया-दोनों में से, केवल आरोपी को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो-एन. सी. बी. द्वारा उस स्थान से पकड़ा गया था जहां नाका को रखा गया था और सह-आरोपी को बाद में गिरफ्तार किया गया था-सह-आरोपी को बार-बार गिरफ्तार किया जा रहा है और उसे मौत की सजा सुनाई जा रही है।**21(ग)** आर. डब्ल्यू. एस.**31 ए (1 ए)** जिसे **14** साल के कठोर कारावास में संशोधित किया गया था-अभियुक्त को यू/एस की सजा सुनाई गई।**21(ग)** निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा दंड सहित बारह वर्ष के लिए कठोर कारावास -

आयोजित किया गया:एन. सी. बी. अधिकारियों द्वारा दर्ज अभियुक्त का इकबालिया बयान यू/एस.67, जिसने सह-अभियुक्त को एक भूमिका के लिए जिम्मेदार ठहराया था और बाद में सह-अभियुक्त का बयान दर्ज किया गया था।⁶⁷ खारिज कर दिए जाते हैं क्योंकि इसका उपयोग एन. सी. बी. अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए इकबालिया बयान के रूप में नहीं किया जा सकता है, जिन्हें "पुलिस अधिकारी" के रूप में माना जाना है।²⁵ साक्ष्य अधिनियम-इसके अलावा, सह-अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए कोई अन्य स्वतंत्र अपराध साबित करने वाला साक्ष्य, इस प्रकार, उसकी दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है-जहां तक अभियुक्त का संबंध है, दोषसिद्धि पूरी तरह से एन. सी. बी. अधिकारियों को दिए गए उसके इकबालिया बयान पर निर्भर नहीं करती है-उसका मामला अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही पर निर्भर करता है, जो सुसंगत हैं और अभियुक्त को कोई लाभ देने के लिए उनके बयानों में कोई भौतिक विरोधाभास नहीं हैं-अभियुक्त द्वारा याचिका कि अभियोजन पक्ष उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में विफल रहा और इस प्रकार, उसकी बेगुनाही साबित करने का बोझ उसके ऊपर वापस नहीं आया-जहां तक मूलभूत तथ्यों को स्थापित करने में विफलता की याचिका का संबंध है, अभियोजन पक्ष उस पर डाली गई जिम्मेदारी को निभाने में सक्षम था ताकि बुनियादी तथ्यों को साबित किया जा सके।³⁵ यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि उसकी मानसिक स्थिति दोषपूर्ण थी, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी-जहां तक अभियुक्त के एन. सी. बी. की हिरासत में होने की याचिका का संबंध है, नाका लगाए जाने से बहुत पहले, कोई मनमानेपन या अनुचित पक्ष नहीं दिखाया गया है।

/

[2023] 14 एस सी आर।

अभियोजन पक्ष के गवाह किसी भी पूर्वाग्रह का दावा करने के लिए-इसे देखते हुए, आरोपी बरी होने का मामला बनाने में विफल रहा, इस प्रकार, दोषसिद्धि का आदेश और निचली

अदालतों द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखा गया, हालांकि, सह-आरोपी बरी हो जाता है।
[पारस 12-14,19,23,27]

दंड प्रक्रिया संहिता, **1973** -धारा **100 (4)**-खोज की अनुमति देने के लिए बंद स्थान के प्रभारी व्यक्ति-स्वतंत्र गवाह की गवाही-धाराओं को देखते हुए अविश्वसनीयता की याचिका।
100(4):

आयोजित किया गया:एस की उप-धारा (4)।100 यह प्रावधान है कि प्रक्रिया की शुद्धता बनाए रखने के लिए, तलाशी लेने से पहले, उस इलाके के कुछ स्वतंत्र और सम्मानित निवासियों को, जहां तलाशी ली जानी है, तलाशी के लिए गवाह के रूप में शामिल किया जाए-तथ्यों पर, जब मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो द्वारा नाका लगाया गया था, तो स्वतंत्र गवाह जांच से जुड़ा था-स्वतंत्र गवाह की गवाही की अविश्वसनीयता की याचिका, यू/एस के प्रावधानों को देखते हुए।100 (4) स्वीकार नहीं किया जा सकता है।[पैरा 24,25]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

तोफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य (2021) 4 एस. सी. सी. 1:[2020] 12 एससीआर 583 – पर भरोसा किया।कन्हैयालाल बनाम भारत संघ 2008 (4) एससीसी 668:[2008] 1 एससीआर 350;

राम सिंह बनाम केंद्रीय मादक पदार्थ ब्यूरो (2011) 11 एस. सी. सी. 347:[2011] 5 एससीआर 967; राज कुमार करवाल बनाम भारत संघ (1990) 2 एससीसी 409: [1990] 2 एससीआर 63; रितेश चक्रवर्ती बनाम स्टेट ऑफ़ एमपी (2006) 12 एससीसी 321:[2006] 6 पूरका.एस. सी. आर. 772; नूर आगा बनाम पंजाब राज्य और दूसरा (2008) 16 एस. सी. सी. 417:[2008] 10 एससीआर 379; भोला सिंह बनाम पंजाब राज्य (2011) 11 एससीसी 653:[2011] 2 एससीआर 642; दिल्ली राज्य बनाम राम अवतार उर्फ राम (2011) 12 एससीसी 207:[2011] 7 एस. सी. आर. 1129; गोरक नाथ प्रसाद बनाम बिहार राज्य (2018) 2 एस. सी. सी. 305; तोफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य (2013) 16 एस. सी. सी. 31:[2013] 9 एस. सी. आर. 962; पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह (1999) 6 एस. सी. सी. 172:[1999] 3 एस. सी. आर. 977; दूध नाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1981) 2 एस. सी. सी. 166:[1981] 2 एससीआर 771, हरियाणा राज्य बनाम राम सिंह (2002) 2 एससीसी 426:[2002] 1 एस. सी. आर. 208; आदमभाई सुलेमानभाई अजमेरी और अन्य बनाम गुजरात राज्य (2014) 7 एससीसी 716:[2014] 7 एस. सी. आर. 48; जूमी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (2014) 11 एस. सी. सी. 355:[2014] 3 एस. सी. आर. 673-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

आपराधिक अपीलीय आधिकारिता :2014 की आपराधिक अपील No.1136।

2012 के सी. आर. एल. ए. No.365 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 2 के निर्णय और आदेश से।

सह

2014 की आपराधिक अपील No.1933

रूप:

मयांक दहिया, कुलदिप सिंह कुचालिया, प्रतिभा प्रकाश जनप्रिय नायक, अक्षय नागराजन, संजय जैन, एड.अपीलार्थी के लिए।

विक्रमजीत बनर्जी, ए. एस. जी., सुश्री रुचि गौर नरूला, गौतम भारद्वाज, अनिरुद्ध शर्मा प्रथम, अरविंद कुमार शर्मा, बी. कृष्ण प्रसाद, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।

सर्वोच्च निर्णय के निर्णय का निर्णय/आदेश

हिमा कोहली, जे.

1. वर्तमान अपीलें 08 जुलाई, 2013 को चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा न्यायाधीश द्वारा तैयार किए गए हत्या संदर्भ 1, मौत की सजा को स्वीकार करने के लिए विशेष अदालत, बलविंदर सिंह द्वारा दायर अपील 2 और सतनाम सिंह के नेतृत्व में अपील 4 एफ. आई. पर निर्णय लेने वाले सामान्य निर्णय से उत्पन्न होती हैं।

1.1 आक्षेपित निर्णय से, बलविंदर सिंह 3 पर लगाई गई मौत की सजा को संदर्भ के अंतर्गत दरकिनार कर दिया गया, जिससे

1 2012 का हत्या संदर्भ सं. 5 जिसका शीर्षक था मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो, चंडीगढ़ क्षेत्रीय इकाई बनाम बलविंदर सिंह @बिंदा

2 सी. आर. ए नं. 2012 का डी-365-डी. बी.

3 2014 की आपराधिक अपील सं. 1136 में अपीलार्थी 4 सी. आर. ए. सं. 2012 का डी-371-डी. बी.

5 2014 की आपराधिक अपील संख्या 1933 में अपीलार्थी

/

[2023] 14 एस सी आर।

संदर्भ और उस पर 14 साल के लिए कठोर कारावास से गुजरने और ₹ 1,50,000-[केवल एक लाख पचास हजार रुपये] का भुगतान करने और चूक में, स्वापक औषधि और

मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 21 (सी) के अंतर्गत एक साल के लिए कठोर कारावास से गुजरने की सजा सुनाई। अभियुक्त द्वारा दायर अपीलों को सजा के क्रम में संशोधन को छोड़कर खारिज कर दिया गया था। दोनों अभियुक्त विशेष अवकाश के माध्यम से इन अपीलों में इस न्यायालय के समक्ष हैं।

I. वास्तविक गुणः

(क) प्रश्न में शामिल व्यक्ति

2. प्रश्न घटना 11 दिसंबर, 2005 की है, जब अभियोजन पक्ष के बयान के अनुसार, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 7 को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति जो प्रतिबंधित पदार्थों की बिक्री में लिप्त थे, वे चंडीगढ़ के एक बस स्टैंड पर प्रतिबंधित पदार्थों की आपूर्ति करने के लिए अमृतसर से एक सफेद रंग की इंडिका कार में यात्रा कर रहे थे। 12 दिसंबर, 2005 को 1 बजे:00 सुबह, एन. सी. बी. की टीम द्वारा चंडीगढ़ में एक नाका रखा गया और दो स्वतंत्र गवाह (मुकेश कुमार और सोनू 8) जाँच में शामिल थे। 3 बजे:15 सुबह, एन. सी. बी. की टीम ने देखा कि सेक्टर 25 से आ रही और सेक्टर 24, चंडीगढ़ की ओर जा रही एक कार नाका की जगह से थोड़ी दूरी पर रुकी और पगड़ी पहने दो लोग कार से उतर गए और भाग गए। हालांकि, तीसरा व्यक्ति, जिसने भी पगड़ी पहनी हुई थी, जिसने बाद में अपना नाम सतनाम सिंह 5 बताया था, कार में बैठा रहा।

2.1. एन. सी. बी. दल के सदस्यों ने वाहन को रोक दिया और स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में सतनाम सिंह 5 की तलाशी ली। कार की तलाशी लेने पर उन्हें दरवाजे के पैनल की गुहा में खाकी टेप में लिपटे दो पैकेट मिले। वाहन की पीछे की सीट के सीट कवर को खोलने पर, खाकी टेप में लिपटे इसी तरह के दो और पैकेट बरामद किए गए। अभियोजन पक्ष का दावा है कि पूछताछ में सतनाम सिंह 5 ने खुलासा किया कि पैकेटों में हेरोइन थी जो वह बलविंदर की सहायता से अमृतसर से लाया था

6 संक्षेप में 'एन. डी. पी. एस. अधिनियम'

7 संक्षेप में 'एन. सी. बी.'

8 पीडब्लू-1

9 सफेद रंग की इंडिका कार जिसका पंजीकरण संख्या एचआर-1-जे-9639 (पी-1 के रूप में चिह्नित) है

बालविंदर सिंह (बिंदा) बनाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो [हिमा कोहली, जे.] 106

सिंह 3 और गुरप्रीत सिंह उर्फ प्रीत उर्फ पंच नाम का एक व्यक्ति चंडीगढ़ में बिक्री के लिए। उन्होंने आगे खुलासा किया कि जब कार नाका से कुछ गज पहले रुकी तो बलविंदर सिंह 3 और सरपंच भाग गए। एन. सी. बी. के अधिकारियों ने सभी चार पैकेटों को जब्त कर लिया और दो प्रतिनिधि नमूने लेने के बाद उन्हें सील कर दिया। पैकेटों के नमूनों पर सतनाम सिंह

5, दो स्वतंत्र गवाहों, खुफिया अधिकारी-बलविंदर कुमार 10 और ओ. पी. शर्मा, अधीक्षक, एन. सी. बी. 11 द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।

((b)) अनुसंधान

2.2. बरामदगी के संबंध में एक पंचनामा 12 मौके पर तैयार किया गया था, जिसे सतनाम सिंह 5 को पढ़ा गया जिन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए। स्वतंत्र गवाहों ने भी ऐसा ही किया। इसके बाद, सतनाम सिंह 5 को गिरफ्तार कर लिया गया और एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत 14 नोटिस जारी करने के बाद उनका बयान 13 दर्ज किया गया। उनकी व्यक्तिगत रूप से भी तलाशी ली गई। स्वतंत्र गवाहों (सोनू 15 और मुकेश 16) के बयान दर्ज किए गए। सतनाम सिंह 5 को इलाका मजिस्ट्रेट के सामने मामले की संपत्ति 17 और दस्तावेजों के साथ पेश किया गया। मामले की संपत्ति गोदाम के प्रभारी अधीक्षक को सौंप दी गई और 18 नमूनों के पार्सल रासायनिक परीक्षक 19 को भेजे गए जिन्होंने बाद में रिपोर्ट 20 भेज दी।

2.3. इस चरण तक सतनाम सिंह 5, यानी बलविंदर सिंह 3 द्वारा नामित सह-आरोपी तस्वीर में कहीं नहीं था। अभियोजन पक्ष का दावा है कि कुछ समय बाद, एन. सी. बी. अधिकारियों को एक समाचार पत्र की रिपोर्ट मिली जिसमें कहा गया था कि बलविंदर सिंह 3 को अमृतसर पुलिस ने एन. डी. पी. एस. मामले में गिरफ्तार किया था और उसे अमृतसर की केंद्रीय जेल में रखा गया था। उक्त सूचना के आधार अंतर्गत बलविंदर सिंह 3 को गिरफ्तार कर लिया गया और उस अंतर्गत 21 का नोटिस जारी किया गया।

10 पीडब्लू-2

11 पीडब्लू-5 (ट्रायल न्यायालय के फैसले में गलत तरीके से पीडब्लू-10 के रूप में उल्लिखित) 12 प्रदर्शनी पी-1/ई

13 पीडब्लू-1/बी प्रदर्शित करें

14 पी-5 का प्रदर्शन करें

15 पीडब्लू-1/डी प्रदर्शित करें

16 पी-9 का प्रदर्शन करें

17 पी-1 प्रदर्शित करें

18 पी-12 का प्रदर्शन करें

19 रसायन परीक्षक श्री.एस. के. मित्तल, पीडब्लू-4 20 प्रदर्शनी पी-11

21 प्रदर्शनी पी-6

/

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67। इसके बाद, उनका स्वैच्छिक बयान 22 दर्ज किया गया और उनके द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

2.4 जाँच के समापन पर, एन. सी. बी. ने न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, चंडीगढ़ के समक्ष एक शिकायत 23 प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि सतनाम सिंह 5 और बलविंदर सिंह 3 ने एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 8, 21, 27 ए और 60 के अंतर्गत दंडनीय अपराध किए थे। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8, 27 ए और 60 के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए थे। 02 जुलाई, 2007 को दोनों अभियुक्तों ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमे का दावा किया।

(ग) विचारण न्यायालय से पहले की प्रक्रियाएँ

2.5. अपनी ओर से, एन. सी. बी. ने सोनू 8 नामक कुछ गवाहों से पूछताछ की, जो एक स्वतंत्र गवाह थे और 12 दिसंबर, 2005 को जब नाका लगाया गया था, तब वे जांच में शामिल हुए थे। सिपाही बलविंदर सिंह 10 जिनका बयान केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, दिल्ली में प्रतिबंधित पदार्थ के नमूने जमा करने से संबंधित है। पी. के. शर्मा 25, तत्कालीन खुफिया अधिकारी, एन. सी. बी. जिन्हें गुप्त सूचना मिली थी जिसके आधार पर नाका लगाया गया था और सतनाम सिंह 5 को गिरफ्तार किया गया था; एस. के. मित्तल 19, रासायनिक परीक्षक, जिन्होंने पीडब्लू-2 10 से नमूना प्राप्त करने के बारे में गवाही दी और 24 फरवरी, 2006 की अपनी रिपोर्ट 20 में कहा कि परीक्षण में, नमूना हेरोइन के लिए सकारात्मक पाया गया और इसमें वजन के हिसाब से डायलेक्टिकल मॉर्फिन का आईडी1 था और ओ. पी. शर्मा 11, अधीक्षक, एन. सी. बी., जिन्होंने नाका बिछाने, आरोपी सतनाम सिंह द्वारा चलाई जा रही इंडिका कार की तलाशी, जिसमें से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया था, रिकवरी-कम-सीजर मेमो 26 की तैयारी और जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ को दिल्ली भेजने के बारे में बताया।

2.6. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने साक्ष्य को बंद करने के बाद, दोनों अभियुक्तों से दंड प्रक्रिया संहिता 28 की धारा 313 के अंतर्गत पूछताछ की गई। वे.

22 प्रदर्शनी-पी-17 23 प्रदर्शनी पी-13

24 संक्षेप में, सी. आर. सी. एल., नई दिल्ली '25 पी. डब्ल्यू. 3

26 प्रदर्शनी पीडब्लू-1/सी 27 प्रदर्शनी पीडब्लू-1/ए 28 संक्षेप में 'Cr.P.C' 107

बालविंदर सिंह (बिंदा) बनाम नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो [हिमा कोहली, जे.] 108

उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया, दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मामले में गलत निहितार्थ का आरोप लगाया। अपने बचाव में, अभियुक्तों ने चार गवाहों, अर्थात् सोरावदीप सिंह 29; नरेश कुमार 30; प्रकाश राम 31 और रविकांत पवार 32, से पूछताछ की। डी. डब्ल्यू.-1 29 और डी. डब्ल्यू.-2 30 को सतनाम सिंह 5 द्वारा यह साबित

करने के लिए बुलाया गया था कि उसके द्वारा अपने मोबाइल नंबर से 11 दिसंबर, 2005 को रात 9:45 बजे चंडीगढ़ में क्षेत्रीय निदेशक के कार्यालय में स्थापित लैंडलाइन नंबर पर 27 सेकंड के लिए कॉल किया गया था, जब वह वास्तव में पुलिस हिरासत में था।

2.7. आवेदकों की ओर से यह तर्क दिया गया कि पीडब्लू-1-सोनू 8 असली अपराधी था जिससे हेरोइन की बरामदगी की गई थी और वह एन. सी. बी. टीम के अधिकारियों को रिश्त देने में कामयाब रहा था, जिसके कारण उन्होंने सतनाम सिंह 5 द्वारा संचालित कार में प्रतिबंधित पदार्थ लगाया था। सतनाम सिंह 5 की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि दो स्वतंत्र गवाहों में से एक, मुकेश कुमार, एन. सी. बी. का स्टॉक गवाह था और दैनिक मजदूरी के रूप में इसकी वेतन सूची में था। डी. डब्ल्यू.-31 और डी. डब्ल्यू.-4 32 की गवाही का उल्लेख किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि मुकेश कुमार को एन. सी. बी. द्वारा दर्ज एक अन्य शिकायत में गवाह के रूप में शामिल किया गया था।

2.8. पूरे साक्ष्य पर चर्चा करने के बाद, 10 मार्च, 2012 के निर्णय के माध्यम से, विशेष न्यायालय, चंडीगढ़ के विद्वान न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया और उन्हें एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 8 के साथ धारा 21 के अंतर्गत दोषी ठहराया। इसके बाद, 15 मार्च, 2012 को सजा की मात्रा पर दलीलें सुनने के बाद, यह देखते हुए कि बलविंदर सिंह 3 को पहले एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 (सी) के अंतर्गत मादक पदार्थों की वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े अपराध और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 31 ए के प्रावधानों को लागू करने के लिए दोषी ठहराया गया था, उन्हें एनडीपीएस अधिनियम की धारा 31 ए (1 ए) के साथ पठित धारा 21 (सी) के अंतर्गत मौत की सजा सुनाई गई थी।

2.9. सह-अभियुक्त सतनाम सिंह 5 पर आते हुए, विशेष न्यायालय, चंडीगढ़ के विद्वान न्यायाधीश ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि वह पंजाब जेल में वार्डन के रूप में काम करने वाला एक सरकारी कर्मचारी था और अपराध करने के समय संगरूर में तैनात था, जिसने अपराध की गंभीरता को और बढ़ा दिया।

29 डीडब्ल्यू 1 30 डीडब्ल्यू 2 31 डीडब्ल्यू 3 32 डीडब्ल्यू 4

/

[2023] 14 एस सी आर।

ऑफ एनस। इसलिए, उन्हें एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 21 (सी) के अंतर्गत बारह साल की अवधि के लिए कठोर कारावास और ₹1 (एक लाख और पचास हजार रुपये) का जुर्माना देने की सजा सुनाई गई और इसके उल्लंघन पर उन्हें तीन साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

(घ) उच्च न्यायालय से पहले की प्रक्रियाएँ

3. उपरोक्त निर्णय से व्यथित होकर दोनों अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। विशेष अदालत, चंडीगढ़ द्वारा अपीलार्थी-बलविंदर सिंह 3 को सुनाई गई मौत की सजा को देखते हुए धारा 366 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत एक हत्या का संदर्भ भी उच्च न्यायालय को भेजा गया था। पूरे साक्ष्य का उच्च न्यायालय द्वारा नए सिरे से विश्लेषण किया गया और इस पर भरोसा किया गया

कन्हैयालाल बनाम भारत संघ 33, राम सिंह बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स 34 और राज कुमार करवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में इस न्यायालय के निर्णय

भारत 35 में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि दोषसिद्धि का आदेश केवल एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत अभियुक्त द्वारा किए गए स्वीकारोक्ति के आधार पर पारित किया जा सकता है और एन. सी. बी. के अधिकारियों के समक्ष इस तरह का स्वीकारोक्ति साक्ष्य में स्वीकार्य थी क्योंकि एन. सी. बी. को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 25 के अर्थ के भीतर "पुलिस अधिकारी" के रूप में नहीं माना जाता है, दोनों अपीलार्थियों को एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अंतर्गत दोषी ठहराया गया था। उक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत दर्ज बलविंदर सिंह 3 और सतनाम सिंह 5 के बयानों पर विचार किया और उन्हें उनके खिलाफ स्वीकारोक्ति के रूप में इस्तेमाल किए जाने के लिए सबूत में स्वीकार्य माना। अभियोजन पक्ष के गवाहों, अर्थात् पीडब्लू-1 8, पीडब्लू-2 10 और पीडब्लू-5 11, जिन्होंने सतनाम सिंह 5 की कार की तलाशी ली थी, जिसके परिणामस्वरूप 4 किलोग्राम हेरोइन की बरामदगी हुई थी, के बयान पर भी उच्च न्यायालय ने भरोसा किया और यह देखा गया कि सतनाम सिंह 5 को एन. सी. बी. अधिकारी द्वारा प्रश्न वाहन में पकड़ा गया था और यह मानने के लिए पर्याप्त सबूत थे कि वह 4 किलोग्राम हेरोइन रखने का दोषी था।

3.1. इसी तरह, बलविंदर सिंह 3 के मामले में, उच्च न्यायालय ने माना कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत दर्ज किया गया उसका स्वीकारोक्ति 19 कन्हैयालाल 33 (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि को देखते हुए स्वीकार्य था। न्यायालय ने कहा कि न तो सतनाम सिंह 5 और न ही बलविंदर सिंह 3 ने याचिका दायर की थी

33 2008 (4) एससीसी 668 34 (2011) 11 एससीसी 347 35 (1990) 2 एससीसी 409 109

बालविंदर सिंह (बिंदा) बनाम नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो [हिमा कोहली, जे.] 110

किए गए इकबालिया बयानों को वापस लेने के लिए कोई औपचारिक आवेदन और उनके इकबालिया बयानों को त्यागने या अभियोजन पक्ष के गवाहों [पीडब्लू-1 8, पीडब्लू-2 10 और पीडब्लू-5 11] की गवाही को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। भले ही बलविंदर सिंह 3 की पहचान पीडब्लू-3 25 और पीडब्लू-5 11 द्वारा नहीं की गई थी, लेकिन उसका बयान 22 एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत विधिवत दर्ज किया गया था और सह-आरोपी सतनाम सिंह 5 ने अपने इकबालिया बयान में यह भी कहा था कि बलविंदर

सिंह 3 अपराध में शामिल था।दोनों इकबालिया बयानों को एक साथ पढ़ने पर, यह मानने के लिए पर्याप्त माना गया कि बलविंदर सिंह 3 अपराध का दोषी था।इसके अलावा यह तथ्य भी जोड़ा गया कि बलविंदर सिंह 3 को पहले ही एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अंतर्गत एक मामले में दोषी ठहराया जा चुका था और सजा सुनाई जा चुकी थी और उक्त दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील उस समय उच्च न्यायालय में लंबित थी।इसलिए, उनकी इस तरह के अपराध करने की प्रवृत्ति थी।उच्च न्यायालय ने राय दी कि केवल इसलिए कि बलविंदर सिंह 3 उस स्थान से ठीक पहले कार से भाग गया था जहां नाका रखा गया था और उसे पकड़ा नहीं जा सका था, उसे बरी करने या हेरोइन के सचेत कब्जे के आरोप से दोषमुक्त करने का आधार नहीं होगा।

3.2.उच्च न्यायालय ने सतनाम सिंह 5 द्वारा पेश किए गए बचाव पक्ष के बयान को खारिज कर दिया कि सोनू 8 [पीडब्लू-1] वास्तविक अपराधी था और उससे ही प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया था, लेकिन वह एन. सी. बी. की टीम को रिश्वत देकर भाग गया जिसने चतुराई से प्रतिबंधित पदार्थ को सतनाम सिंह 5 द्वारा संचालित कार में लगाया था।याचिका में कहा गया है कि अन्य स्वतंत्र गवाह, मुकेश कुमार, हालांकि अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पेश किया गया था और पेश नहीं किया गया था, लेकिन वह भी एन. सी. बी. का मुख्य गवाह था, लेकिन वह भी अयोग्य पाया गया।उच्च न्यायालय ने कहा कि मुकदमों के दौरान मुकेश कुमार से पूछताछ नहीं की गई क्योंकि अपीलकर्ताओं ने उन्हें जीत लिया था।उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, बलविंदर सिंह 3 और सतनाम सिंह 5 दोनों को संबंधित तिथि पर वाणिज्यिक मात्रा में हेरोइन के होश में पाया गया और निचली न्यायालय द्वारा उन्हें एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 8 के साथ पठित धारा 21 (सी) के अंतर्गत दंडनीय अपराध करने का दोषी ठहराते हुए वापस किए गए आदेश को बरकरार रखा गया।उच्च न्यायालय ने सतनाम सिंह 5 को 12 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा का आदेश दिया था।हालांकि, अपीलार्थी-बलविंदर सिंह 3 को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 31 ए के अंतर्गत दोहराए जाने के लिए दी गई मौत की सजा को बहुत कठोर सजा माना गया।नतीजतन, बलविंदर सिंह 3 को दी गई मौत की सजा को दरकिनार कर दिया गया और उच्च न्यायालय ने उन्हें 14 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई।

/

[2023] 14 एस सी आर।

₹1,50,000/- [केवल एक लाख पचास हजार रुपये] और शुल्क का भुगतान न करने पर, एक वर्ष के लिए कारावास की सजा होती है।उपरोक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर, अपीलकर्ताओं ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

II दलों के लिए विद्वानों द्वारा प्रतिपादित तर्क

(क) बालविंदर सिंह 3 और सतनाम सिंह 5 के लिए परामर्श द्वारा प्रस्तुतियां

4. अपीलार्थी-बलविन्दर सिंह 3 के विद्वान वकील श्री मयांक दहिया ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को पूरी तरह से सह-अभियुक्त सतनाम सिंह 5 द्वारा एन. सी. बी. अधिकारियों के समक्ष किए गए स्वीकारोक्ति के कथित बयान के आधार पर दोषी ठहराया गया था, जो अब तोफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य 36 के मामले में इस न्यायालय के फैसले के आलोक में विधि ी रूप से स्वीकार्य नहीं है। यह कहा गया था कि उच्च न्यायालय इस तथ्य से प्रभावित था कि उस समय बलविंदर सिंह 3 एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अंतर्गत तीन अन्य मामलों का सामना कर रहा था, लेकिन बाद में, उसे सभी मामलों में संदेह का लाभ दिए जाने पर बरी कर दिया गया था। हालाँकि, तत्काल मामले में, वह वर्तमान अपील के लंबित रहने के दौरान उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सजा से पहले ही गुजर चुका है।

4.1 बलविंदर सिंह 3 के विद्वान वकील द्वारा दिए गए इसी तरह के तर्क के अलावा कि एन. सी. बी. अधिकारियों के समक्ष सतनाम सिंह 5 द्वारा दिए गए कबूलनामे का बयान विधि ी रूप से स्वीकार्य नहीं है और तोफान सिंह 36 (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के हालिया फैसले को देखते हुए उनके खिलाफ सबूत में नहीं पढ़ा जा सकता है, उक्त अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री अक्षय नागराजन ने मुख्य रूप से तथ्यों के आधार पर आक्षेपित फैसले की आलोचना की है। सबसे पहले, कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अंतर्गत किया गया अपराध एक गंभीर अपराध है, अभियुक्त को क़ानून के अंतर्गत प्रदान किए गए सभी प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के लिए सख्त अनुपालन और सख्त जांच की आवश्यकता होती है और तत्काल मामले में, क्योंकि अभियोजन पक्ष प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में विफल रहा, बोझ अभियुक्त पर नहीं पड़ा। उक्त निवेदन को पुष्ट करने के लिए, विद्वान वकील ने उद्धृत किया है

रितेश चक्रवर्ती बनाम एम. पी. राज्य 37; नूर आगा बनाम पंजाब राज्य और

36 (2021) 4 एससीसी 1 37 (2006) 12 एससीसी 321 111

बालविंदर सिंह (बिंदा) बनाम नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो [हिमा कोहली, जे.] 112

अन्य 38; भोला सिंह बनाम पंजाब राज्य 39; दिल्ली राज्य बनाम राम अवतार उर्फ राम 40; और गोरक नाथ प्रसाद बनाम बिहार राज्य 41।

4.2 दूसरी याचिका यह है कि अभियोजन पक्ष द्वारा तैयार की गई पूरी कहानी अस्थिर है क्योंकि इसमें शामिल होने वाले स्वतंत्र गवाहों की पृष्ठभूमि अस्पष्ट है और उनकी गवाही पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। सोनू 8 की गवाही पर सवाल उठाया गया है और यह कहा गया है कि उसे आईडी 1 दंड प्रक्रिया संहिता 100 (4) के संदर्भ में एक स्वतंत्र गवाह के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने उक्त गवाह की विश्वसनीयता का पुनर्मूल्यांकन करने और खुद को संतुष्ट करने में विफल रहने में गलती की है कि क्या वह वास्तव में एक स्वतंत्र गवाह था। तीसरा, यह तर्क दिया गया कि अन्य स्वतंत्र गवाह, मुकेश कुमार को गवाहों की सूची में रखा गया था, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा इस

कारण से पूछताछ नहीं की गई कि वह एक स्टॉक गवाह था, जैसा कि डीडब्ल्यू-31 और डीडब्ल्यू-4 32 के बयान से पता चलता है। इसके बाद, यह तर्क दिया गया कि मामले की संपत्ति 17, मुख्य रूप से प्रतिबंधित पदार्थ जो कथित रूप से बरामद किया गया था, को ठीक से नहीं संभाला गया था, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि पंचनामा 12 में प्रतिबंधित पदार्थ को एक ऐसे पदार्थ के रूप में वर्णित किया गया था जो सफेद रंग का था, लेकिन उनकी गवाही में, रासायनिक परीक्षक 19 ने प्रतिबंधित पदार्थ को गांठों के साथ हल्के भूरे रंग का बताया। बचाव पक्ष द्वारा बताए गए प्रतिबंधित पदार्थ में यह विसंगति मामले की जड़ तक जाती है।^{4.3} अंत में, सतनाम सिंह 5 की ओर से यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय को बचाव पक्ष के इस कथन को पूरी तरह से खारिज नहीं करना चाहिए था कि यह सोनू 8 [पीडब्लू-1] था जिसके पास प्रतिबंधित पदार्थ पाया गया था और उसके विरचित एन. सी. बी. अधिकारियों को रिश्त देने पर उसे छोड़ दिया गया था, जबकि सतनाम सिंह 5, जो निर्दोष था, को फंसाया गया था। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि डी. डब्ल्यू.-2 30 के बयान से साबित होता है कि जिस लैंडलाइन नंबर पर एन. सी. बी. अधिकारियों द्वारा 11 दिसंबर, 2005 को रात 1 बजे सतनाम सिंह 5 के मोबाइल फोन से फोन किया गया था, वह क्षेत्रीय निदेशक, एन. सी. बी., चंडीगढ़ का आधिकारिक नंबर था और एक बार रिकॉर्ड में लाया गया उक्त सबूत, उच्च न्यायालय के लिए एन. सी. बी. के इस कथन को खारिज करने के लिए पर्याप्त था कि वे 12 दिसंबर, 2005 को सुबह 2 बजे नाका पर पहली बार सतनाम सिंह 5 से मिले थे। विद्वान वकील ने प्रस्तुत करके निष्कर्ष निकाला

38 (2008) 16 एससीसी 417 39 (2011) 11 एससीसी 653 40 (2011) 12 एससीसी 207 41 (2018) 2 एससीसी 305

/

[2023] 14 एस सी आर।

कि यद्यपि सतनाम सिंह 5 पहले ही उस पर अधिरोपित सजा से गुजर चुका है, लेकिन वह गुण-दोष के आधार पर बरी करने के लिए अपील पर जोर दे रहा है क्योंकि अपीलकर्ता एक सरकारी कर्मचारी था जिसे दोषी ठहराए जाने पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, जो आदेश, यदि उलट दिया जाता है, तो उसे अपने सेवा लाभों के संबंध में राहत का हकदार बना देगा।

(ख) उत्तरदाता, एन. सी. बी. के लिए लीनर्ड काउंसल द्वारा बनाए गए विषय

5. दूसरी ओर, प्रतिवादी-एन. सी. बी. के विद्वान वकील ने आक्षेपित फैसले का समर्थन किया है और कहा है कि बलविंदर सिंह 3 और सतनाम सिंह 5 को दोषी ठहराने के लिए एन. सी. बी. द्वारा रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत लाए गए थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि एन. सी. बी. द्वारा पेश किए गए गवाहों में से किसी को भी पेश नहीं किया गया था, जैसा कि आरोप लगाया गया था; कि एन. सी. बी. ने अपीलार्थियों के खिलाफ एक प्रथम दृष्टया मामला सफलतापूर्वक

स्थापित किया था, जिसके बाद उनकी बेगुनाही साबित करने के लिए बोझ उन पर स्थानांतरित हो गया था और वे उक्त बोझ का निर्वहन करने में बुरी तरह विफल रहे थे; कि अभियोजन पक्ष ने एन. डी. पी. एस. अधिनियम की कठोरता को आकर्षित करने के लिए बुनियादी तथ्यों को पूरी तरह से साबित कर दिया था और अधिनियम कारण, अर्थात् अपीलार्थियों द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ का कब्जा, उन्हें उस अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए आश्वस्त रूप से स्थापित किया गया था जिसके लिए उन पर आरोप लगाया गया था। इस प्रकार यह कहा गया कि आक्षेपित निर्णय हस्तक्षेप के योग्य नहीं है।

III विश्लेषण और चर्चा

(क) टफान सिंह के निर्णय का संकेत

6. हमने आक्षेपित फैसले और अभिलेख का अध्ययन किया है और पक्षों के विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्कों पर विचारपूर्वक विचार किया है।

7. जब वर्ष 2013 में उच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान मामले पर विचार किया गया था, तो उसने प्रत्यर्थी-एन. सी. बी. के लिए विद्वान वकील द्वारा दी गई दलीलों को स्वीकार कर लिया था कि राजस्व खुफिया विभाग के अधिकारी जो अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी प्रभारी की शक्तियों के साथ निहित हैं, वे साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अर्थ के भीतर "पुलिस अधिकारी" नहीं हैं और इसलिए यह अभिनिर्धारित किया कि जांच के दौरान ऐसे अधिकारी द्वारा दर्ज एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अंतर्गत अपराध के आरोपी व्यक्ति का इकबालिया बयान उसके खिलाफ स्वीकार्य है। उक्त तर्क को 113 के आलोक में उच्च न्यायालय का समर्थन मिला था।

बालविंदर सिंह (बिंदा) बनाम नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो [हिमा कोहली, जे.] 114 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

कन्हैयालाल 33 (ऊपर) और राज कुमार करवाल 35 (ऊपर) मामले में इस अदालत के निर्णय जहां यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अभियुक्त द्वारा एन. सी. बी. के एक अधिकारी के समक्ष किया गया स्वीकारोक्ति साक्ष्य में स्वीकार्य है क्योंकि उक्त अधिकारी को साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अर्थ के भीतर "पुलिस अधिकारी" के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत किसी अभियुक्त द्वारा किए गए एकमात्र स्वीकारोक्ति पर दोषसिद्धि कायम रखी जा सकती है। राम सिंह 34 (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय द्वारा लिए गए इसी तरह के दृष्टिकोण को उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय को मजबूत करने के लिए उद्धृत किया गया था कि अपीलकर्ताओं द्वारा एन. सी. बी. के अधिकारियों के समक्ष किए गए इकबालिया बयान साक्ष्य में स्वीकार्य थे, जो स्वैच्छिक प्रकृति के थे।

8. हालाँकि, वर्ष 2013 से पुल के अंतर्गत बहुत पानी बह गया है। वर्ष 2020 में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने तोफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य 42 मामले में एक खंड

पीठ के एक संदर्भ आदेश का जवाब दिया और कन्हैयालाल 33 (ऊपर) और राज कुमार करवाल 35 (ऊपर) के अनुपात की फिर से जांच की ताकि यह तय किया जा सके कि एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत किसी मामले की जांच करने वाला अधिकारी 'पुलिस अधिकारी' के रूप में योग्य होगा या नहीं। अन्य संबंधित मुद्दा जिसकी तोफान सिंह 36 (उपरोक्त) मामले में बड़ी पीठ द्वारा जांच की गई थी, वह यह था कि क्या एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए बयान को इकबालिया बयान के रूप में माना जा सकता है या नहीं, भले ही अधिकारी को "पुलिस अधिकारी" के रूप में नहीं माना जाता है।

9. एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में कानूनी स्थिति की विस्तृत जांच के बाद, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 जैसे राजस्व कानूनों के साथ-साथ साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 और धारा 25, न्यायमूर्ति नरीमन द्वारा लिखित बहुमत निर्णय निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचा:

“155. इस प्रकार, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि धारा 42 या धारा 53 के अंतर्गत नामित एक अधिकारी के समक्ष दिया गया इकबालिया बयान एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने का आधार हो सकता है, बिना किसी गैर-बाधा खंड के साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 को समाप्त करना, और बिना किसी सुरक्षा उपायों के, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 20 (3) और 21 में निहित संवैधानिक गारंटी का सीधा उल्लंघन होगा।

42 (2013) 16 एससीसी 31

156. कन्हैयालाल बनाम भारत संघ के मामले में निर्णय ,

(2008) 4 एससीसी 668:(2008) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 474] इसके बाद राज कुमार करवाल [राज कुमार करवाल बनाम भारत संघ, (1990) 2 एस. सी. सी. 409:1990 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 330] पैरा 44 और 45 में। ऊपर हमारे द्वारा बताए गए कारणों के कारण, ये दोनों निर्णय विधि को सही ढंग से नहीं बताते हैं, और इस प्रकार हमारे द्वारा खारिज कर दिए जाते हैं। अन्य निर्णय जो स्पष्ट रूप से इन निर्णयों को संदर्भित करते हैं और उन पर निर्भर करते हैं, या इन निर्णयों द्वारा निर्धारित सिद्धांतों पर, हमारे द्वारा दिए गए कारणों से भी खारिज कर दिए जाते हैं।

157. दूसरी ओर, इस निर्णय में हमारे द्वारा दिए गए कारणों के लिए, नूर आगा [नूर आगा बनाम पंजाब राज्य, (2008) 16 एस. सी. सी. 417:(2010) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 748] और निर्मल सिंह पहलवान बनाम निरीक्षक,

सीमा शुल्क [निर्मल सिंह पहलवान बनाम निरीक्षक, सीमा शुल्क, (2011) 12 एससीसी

298 : (2012) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 555] विधि में सही हैं। 158. हम संदर्भ का जवाब देते हुए कहते हैं:

158.1. यह कि जिन अधिकारियों को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत शक्तियां दी गई हैं, वे साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अर्थ के भीतर "पुलिस अधिकारी" हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें दिए गए किसी भी इकबालिया बयान को साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिबंधित किया जाएगा, और एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अंतर्गत किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।

158.2. कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत दर्ज किए गए बयान का उपयोग एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अंतर्गत अपराध के मुकदमे में इकबालिया बयान के रूप में नहीं किया जा सकता है।

[जोर दिया गया]

10. उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए जो यह घोषणा करता है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत शक्तियों के साथ निवेश किए गए किसी अधिकारी को किसी भी अभियुक्त द्वारा दिया गया इकबालिया बयान इस कारण से वर्जित है कि ऐसे अधिकारी साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अर्थ के भीतर "पुलिस अधिकारी" हैं, एक अभियुक्त द्वारा दिए गए और एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत दर्ज किए गए बयान को एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अंतर्गत अपराध के मुकदमे में इकबालिया बयान के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

115

बालविंदर सिंह (बिंदा) बनाम नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो [हिमा कोहली, जे.] 116 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

(ख) बालविंदर सिंह के मामले पर टोफान सिंह के प्रभाव का प्रभाव

11. अब जब टोफान सिंह के मामले 36 (ऊपर) में यह घोषित किया गया है कि कन्हैयालाल 33 (ऊपर) और राज कुमार करवाल 35 (ऊपर) के मामले में दिए गए फैसलों में सही कानूनी स्थिति नहीं बताई गई है और वे खारिज हो गए हैं, तो बलविंदर सिंह 3 के खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित पूरा मामला ताश के पत्तों की तरह गिर जाता है। यह विवाद में नहीं है कि बलविंदर सिंह 3 को एन. सी. बी. के अधिकारियों द्वारा उस स्थान से नहीं पकड़ा गया था जहाँ नाका रखा गया था और अकेले सतनाम सिंह 5 को इंडिका कार में पकड़ा गया था। अभियोजन पक्ष का कहना है कि सतनाम सिंह 5 की गिरफ्तारी के बाद, उसका बयान 13 एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत दर्ज किया गया था, जिसमें उसने सह-आरोपी-बलविंदर सिंह 3 और सरपंच को एक विशिष्ट भूमिका के लिए जिम्मेदार ठहराया था। एन. सी. बी. के अधिकारियों ने दावा किया कि वे दोनों की तलाश कर रहे थे

क्योंकि वे मौके से भागने में कामयाब रहे थे। जबकि सरपंच को गिरफ्तार नहीं किया जा सका, एन. सी. बी. अधिकारियों को अखबार में आई खबरों से पता चला कि बलविंदर को अमृतसर पुलिस ने एन. डी. पी. एस. मामले में गिरफ्तार किया था और उसे अमृतसर की केंद्रीय जेल में रखा गया था। तत्काल मामले में बलविंदर सिंह 3 को हिरासत में लेने के लिए संबंधित न्यायालय से अनुमति ली गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत उन पर 21 का नोटिस जारी किया गया और उनका बयान 22 दर्ज किया गया। उनके बयान 22 को इकबालिया बयान मानते हुए, बलविंदर सिंह 3 को गिरफ्तार कर लिया गया।

12. एक बार जब सह-अभियुक्त सतनाम सिंह 5 का एन. सी. बी. अधिकारियों द्वारा एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत दर्ज किया गया इकबालिया बयान 13, जिसने बलविंदर सिंह 3 को एक भूमिका के लिए जिम्मेदार ठहराया था और बाद में एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत खुद बलविंदर सिंह 3 का 22 दर्ज किया गया बयान तोफान सिंह 36 (उपरोक्त) में निर्धारित विधि के आलोक में खारिज कर दिया जाता है, तो अभियोजन पक्ष द्वारा बलविंदर सिंह 3 को एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अंतर्गत दोषी ठहराने के लिए कोई अन्य स्वतंत्र साक्ष्य सामने नहीं लाया गया है। जाँच के दौरान एन. सी. बी. के अधिकारियों के सामने दर्ज किए गए उक्त इकबालिया बयान 13 और 22 को नजरअंदाज करने पर, बलविंदर सिंह 3 और जिस अपराध के लिए उन पर आरोप लगाया गया है, उसके बीच महत्वपूर्ण संबंध निर्णायक रूप से सामने आता है और उनके दोषसिद्धि आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है।

13. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, हमारी राय है कि बलविंदर सिंह 3 एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अंतर्गत हेरोइन की वाणिज्यिक मात्रा को जानबूझकर रखने के आरोप से बरी होने का हकदार है। तदनुसार आदेश दिया।

(ग) सतनाम सिंह का मामला अलग-अलग भोजन पर कैसे लगाया जाता है

14. इसके बाद हम अपीलार्थी सतनाम सिंह 5 के मामले पर आते हैं। पुनः, जैसा कि बलविंदर सिंह 3 के मामले में, सतनाम सिंह 5 द्वारा दिए गए और एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत दर्ज किए गए बयान 13 को पूरी तरह से खारिज करना होगा क्योंकि इसका उपयोग एन. सी. बी. अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए इकबालिया बयान के रूप में नहीं किया जा सकता है, जिन्हें तोफान सिंह के मामले 3,6 (उपरोक्त) में फैसले के संदर्भ में साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत "पुलिस अधिकारी" के रूप में माना जाना है। लेकिन बलविंदर सिंह 3 के मामले के विपरीत, सतनाम सिंह 5 की दोषसिद्धि केवल एन. सी. बी. अधिकारियों को दिए गए उसके इकबालिया बयान 13 पर निर्भर नहीं करती है। उनका मामला एक अलग आधार पर है क्योंकि यह तीन प्रमुख अभियोजन गवाहों, सोनू 8 [पीडब्लू-1], पी. के. शर्मा 25 [पीडब्लू-3] और ओ. पी. शर्मा 11 [पीडब्लू-5] की गवाही सहित अन्य प्रासंगिक कारकों पर भी निर्भर करता है। हम नीचे चर्चा करने का प्रस्ताव

करते हैं कि जब उनकी गवाही की सावधानीपूर्वक जांच की जाती है, तो यह दर्शाता है कि वे सुसंगत और अचूक रहे थे। अपीलार्थी को कोई लाभ देने के लिए इस न्यायालय के लिए उनके बयानों में कोई भौतिक विरोधाभास या विचलन नहीं दिखाई देता है-सतनाम सिंह 5.

(घ) "संभाव्यता की तैयारी" के संदर्भ में कारणवश दोहरे होने का प्रमाण: कानूनी स्थिति

15. हम पहले स्थापित विधि के आधार पर परीक्षण कर सकते हैं, अपीलार्थी के विद्वान वकील-सतनाम सिंह 5 द्वारा की गई याचिका कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में विफल रहा था और इसलिए, उसकी बेगुनाही साबित करने का बोझ उसके ऊपर वापस नहीं आया। नूर आगा 38 (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की संवैधानिक वैधता और अभियोजन पक्ष पर सबूत के बोझ के मानक और सीमा सहित कई प्रश्नों पर निर्णय लेने की आवश्यकता थी। एक व्यापक चर्चा के बाद, इस न्यायालय ने एन. डी. पी. एस. अधिनियम 43 की धारा 35 और 54 के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, लेकिन यह निर्णय दिया कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों और

43 35. दोषपूर्ण मानसिक स्थिति का अनुमान-(1) किसी अपराध के लिए किसी भी अभियोजन में

इस अधिनियम के अंतर्गत, जिसमें अभियुक्त की दोषी मानसिक स्थिति की आवश्यकता होती है, न्यायालय ऐसी मानसिक स्थिति के अस्तित्व का अनुमान लगाएगा, लेकिन यह अभियुक्त के लिए इस तथ्य को साबित करने के लिए एक बचाव होगा कि उस अभियोजन में अपराध के रूप में आरोपित कार्य के संबंध में उसकी ऐसी कोई मानसिक स्थिति नहीं थी।

117

बालविंदर सिंह (बिंदा) बनाम नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो [हिमा कोहली, जे.] 118

उसमें निर्धारित दंड कठोर हैं, अभियोजन पक्ष पर डाले गए मूलभूत तथ्यों को साबित करने के लिए बोझ की सीमा अधिक कठिन होनी चाहिए। लिया गया विचार यह था कि अदालतों को एक गहन जांच परीक्षण करना होगा और "सभी उचित संदेह से परे सबूत" के बारे में खुद को संतुष्ट करना होगा। आपराधिक न्यायशास्त्र के अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत पर जोर दिया गया था कि सबूत की डिग्री अधिक गंभीर होगी और दोषी ठहराने के लिए उच्च स्तर का आश्वासन आवश्यक होगा।

अभियुक्त। [यह भी देखें -पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह 44, रितेश चक्रवर्ती बनाम एमपी राज्य 45 और भोला सिंह 39 (ऊपर)]।

16. इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि प्रारंभिक बोझ अभियोजन पक्ष पर डाला जाता है ताकि उन आवश्यक कारकों को स्थापित किया जा सके जिन पर उसका मामला आधारित है। अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त भार का निर्वहन करने के बाद, अपनी बेगुनाही साबित करने की जिम्मेदारी अभियुक्त पर आ जाती है। हालाँकि, अभियुक्त के लिए अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए आवश्यक सबूत का मानक, अभियोजन पक्ष से अपेक्षित उच्च नहीं है। नूर आगा 38 (ऊपर) मामले में पीठ की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति सिन्हा ने कहा था कि:

“58. जबकि अभियोजन पक्ष पर अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए आवश्यक सबूत का मानक "सभी उचित संदेह से परे" है, लेकिन यह है

स्पष्टीकरण-इस खंड में "दोषपूर्ण मानसिक स्थिति" में इरादे का उद्देश्य, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास या विश्वास करने का कारण शामिल है।

(2) इस धारा के प्रयोजन के लिए, एक तथ्य को केवल तभी साबित कहा जाता है जब न्यायालय मानता है कि यह एक उचित संदेह से परे है, न कि केवल जब इसका अस्तित्व संभावना की अधिकता से स्थापित होता है।

54. अवैध वस्तुओं के कब्जे से अनुमान-इस अधिनियम के अंतर्गत परीक्षणों में, यह कर सकता है

जब तक और जब तक इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है, यह माना जाएगा कि अभियुक्त ने इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित के संबंध में अपराध किया है -

(क) कोई मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ;

(ख) जिस भूमि पर उसने खेती की है, उस पर उगने वाला कोई भी अफीम का खसखस, भांग का पौधा या कोका का पौधा;

(ग) विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया कोई उपकरण या बर्तनों का कोई समूह जो किसी मादक दवा या मादक पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ के निर्माण के लिए विशेष रूप से अपनाया गया हो; या

(घ) ऐसी कोई भी सामग्री जो किसी मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ के निर्माण की दिशा में किसी भी प्रक्रिया से गुजरी है, या उस सामग्री के अवशेष जिनसे कोई मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ का निर्माण किया गया है, जिसके लिए वह संतोषजनक रूप से जिम्मेदार नहीं है।

44 (1999) 6 एस. सी. सी 172

45 (2006) 12 एस. सी. सी. 321

/

[2023] 14 एस सी आर।

“अभियुक्त पर "संभावना की प्रधानता"। यदि अभियोजन पक्ष अधिनियम की धारा 35 की कठोरता को आकर्षित करने के लिए मूलभूत तथ्यों को साबित करने में विफल रहता है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी के पास प्रतिबंधित पदार्थ का अधिकार है। ”

शीर्षक वाले मामले में चर्चा का सार यह था कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 54 के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए, अभियोजन पक्ष के लिए यह आवश्यक है कि वह आरोपी द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ रखने के तत्व को स्थापित करे ताकि आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बोझ स्थानांतरित किया जा सके। प्रतिबंधित पदार्थ के कब्जे के इस पहलू को अभियोजन पक्ष द्वारा उचित संदेह से परे साबित करना होगा।

(ङ) आधारभूत तथ्यों को स्थापित करने में विफलता का अनुरोध

17. अपीलार्थी के विद्वान वकील सतनाम सिंह 5 ने कहा कि अभियोजन पक्ष सतनाम सिंह 5 द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ के कब्जे के अंतर्निहित तथ्यों को स्थापित करने में विफल रहा और इसलिए, सबूत का भार अभियुक्त पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था, अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए योग्यता से रहित पाया गया है। अभियोजन पक्ष इस तथ्य को स्थापित करने में सफल रहा कि यह अपीलकर्ता-सतनाम सिंह 5 था जो कार 9 चला रहा था, जब उसे उस स्थान पर रोका गया था जहां संबंधित तिथि पर एन. सी. बी. अधिकारी द्वारा नाका रखा गया था। अपीलार्थी सतनाम सिंह 5 की तलाशी लेने पर कार 9 के पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक फोटोकॉपी बरामद की गई। वह कार 9 का मालिक था। कार 9 की तलाशी दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में एन. सी. बी. अधिकारी द्वारा ली गई थी। अपीलार्थी द्वारा चलाई जा रही कार 9 से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया था-स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में सतनाम सिंह 5 और पी. के. शर्मा, एक राजपत्रित अधिकारी सी. ई. 25, जो एन. सी. बी. टीम का हिस्सा थे। भले ही दो स्वतंत्र गवाहों में से एक [मुकेश कुमार] मुकर गया था और अभियोजन पक्ष द्वारा उसे हटा दिया गया था, लेकिन दूसरे स्वतंत्र गवाह [सोनू 8] की गवाही सुसंगत थी और आरोपी द्वारा अपनी जिरह के दौरान कुछ भी सामग्री प्राप्त नहीं की जा सकी थी।

18. रासायनिक परीक्षक [एस. के. मित्तल 22] के बयान के माध्यम से, अभियोजन पक्ष ने उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट 20 को सफलतापूर्वक साबित कर दिया जिसमें कहा गया था कि नमूनों 18 की जांच करने पर, अपीलार्थी की कार 9-सतनाम सिंह 5 से बरामद बैग से निकाले गए पदार्थ हेरोइन थे। खींचे गए और सील किए गए 18 नमूनों में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई और 119 की गवाही मिली।

बालविंदर सिंह (बिंदा) बनाम नाकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो [हिमा कोहली, जे.] 120

सिपाही बलविंदर कुमार 10 ने इस तथ्य की पुष्टि की कि वह 18 नमूनों को अपने साथ ले गया था और उन्हें 14 दिसंबर, 2005 को सी. आर. सी. एल., नई दिल्ली में जमा कर दिया था, जिसमें सभी मुहरें बरकरार थीं।

19. उपरोक्त विवरण को देखते हुए, हमारी राय है कि अभियोजन पक्ष मूलभूत तथ्यों को साबित करने के लिए उस पर डाली गई जिम्मेदारी का निर्वहन करने में सक्षम था। इस प्रकार, यह साबित करने का प्रारंभिक भार कि अपीलार्थी-सतनाम सिंह 5 को इस बात की जानकारी थी कि कार 9 का स्वामित्व और संबंधित समय पर उसके द्वारा चलाई जा रही गाड़ी का उपयोग मादक पदार्थों के परिवहन के लिए किया जा रहा था, उसे छोड़ दिया गया। एक बार जब यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश किए थे कि आरोपी-सतनाम सिंह 5 को जानकारी थी, तो एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत उसके खिलाफ यह धारणा बनानी होगी कि उस अपराध के लिए उस पर आरोप लगाने के लिए वह दोषी मानसिक स्थिति में था, जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया था। 20. जैसा कि इस

न्यायालय द्वारा राम अवतार उर्फ रामा 40 (उपरोक्त) के मामले में कहा गया है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत दोषसिद्धि प्राप्त करने के लिए निषिद्ध पदार्थ का कब्जा एक अनिवार्य शर्त है और इस तरह की निषिद्ध वस्तु को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों के अनुसार बरामद किया जाना चाहिए, जो कि अभियुक्त के पक्ष में एक वैधानिक सुरक्षा है; अन्यथा वसूली स्वयं विधि में दूषित हो जाएगी।

21. अपीलार्थी-सतनाम सिंह 5 की ओर से यह तर्क दिया गया कि नीचे की दोनों अदालतों ने उनके द्वारा इस आशय के बचाव को खारिज करने में गलती की है कि यह सोनू 8 ही था जो वास्तविक अपराधी था और जिसे एन. सी. बी. अधिकारियों द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ के साथ पकड़ा गया था, लेकिन उसे एन. सी. बी. अधिकारियों को रिश्वत देने पर छोड़ दिया गया था, यह संभावना की प्रधानता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है और दोनों अदालतों द्वारा ठोस सबूत के माध्यम से किसी भी पुष्टि के अभाव में उचित रूप से अविश्वास किया गया है।

(च) एन. सी. बी. की कस्टडी में आरोपी होने का अनुरोध नाका पर मुकदमा होने से बहुत पहले

22. अपीलार्थी द्वारा ली गई एक अन्य याचिका-सतनाम सिंह 5 यह है कि वह 11 दिसंबर, 2005 को नाका लगाए जाने से बहुत पहले ही एन. सी. बी. अधिकारियों की हिरासत में था। उनके द्वारा पेश किए गए गवाह, सोरावदीप सिंह 19 [डी. डब्ल्यू.-1] ने यह साबित करने के लिए गवाही दी कि 11 दिसंबर, 2005 को उनके मोबाइल नंबर से एक लैंडलाइन नंबर पर कॉल किया गया था, जब उन्हें पहले ही एन. सी. बी. अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिया जा चुका था।

/

[2023] 14 एस सी आर।

चंडीगढ़ में क्षेत्रीय निदेशक के कार्यालय में, कोई सहायता नहीं थी क्योंकि अपीलार्थी द्वारा बुलाए गए मोबाइल फोन बिल विधि के अनुसार साबित नहीं हुए थे। ट्रायल न्यायालय ने कहा कि प्रश्न 46 में बिल केवल एक कंप्यूटर-जनरेटेड था। बुलाए गए गवाह द्वारा बिल से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे और बिल पर किसी भी प्राधिकरण के हस्ताक्षर नहीं थे, यहां तक कि यह साबित करने के लिए कि अपीलार्थी द्वारा दावा किया गया मोबाइल फोन नंबर-सतनाम सिंह 5, उनके नाम पर था। हम एक अलग दृष्टिकोण लेने का कोई कारण नहीं देखते हैं।

23. विद्वान वकील ने दूध नाथ में लिए गए फैसलों पर भरोसा जताया

पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 47, हरियाणा राज्य बनाम राम सिंह 48, आदमभाई सुलेमानभाई अजमेरी और अन्य बनाम गुजरात राज्य 49 और जुमी

और अन्य बनाम हरियाणा राज्य 50 यह आग्रह करना कि बचाव पक्ष के गवाह अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए गवाहों के साथ समान व्यवहार के हकदार हैं और बचाव पक्ष के गवाहों की तुलना में अभियोजन पक्ष के गवाहों के लिए अलग-अलग मापदंड निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं, आपराधिक न्यायशास्त्र का एक अच्छी तरह से तय सिद्धांत है, लेकिन अपीलार्थी के मामले को आगे नहीं ले जा सकता है-सतनाम सिंह 5 क्योंकि निचली न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ प्रतिकूल अनुमान लगाने से पहले बचाव पक्ष के गवाहों की गवाही का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया है। उच्च न्यायालय ने बचाव पक्ष के गवाहों की पूरी गवाही को देखने के लिए भी मेहनत की है और उसके बाद ही निचली अदालत द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का समर्थन किया है। अपीलार्थी सतनाम सिंह की ओर से अभियोजन पक्ष के गवाहों को कोई पक्षपात का दावा करने के लिए कोई मनमानेपन या अनुचित पक्ष नहीं दिखाया गया है।

(छ) स्वतंत्र गवाह, एस. ओ. एन. यू. के परीक्षण की अविश्वसनीयता का अनुरोध

24. जहाँ तक अपीलार्थी के विद्वान वकील सतनाम सिंह 5 के इस तर्क का संबंध है कि सोनू 8 की गवाही को आई. डी. 1 की धारा 100 (4) के अंतर्गत प्रावधानों को देखते हुए एक स्वतंत्र गवाह के रूप में नहीं माना जा सकता है, हमारा विचार है कि उक्त याचिका में कोई आधार नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता धारा 100 (4) जो अध्याय VII के अंतर्गत आती है जिसका शीर्षक है "मजबूर करने की प्रक्रिया"।

चीज़ों का उत्पादन इस प्रकार है:

46 Ex.DW-1/A

47 (1981) 2 एससीसी 166 48 (2002) 2 एससीसी 426 49 (2014) 7 एससीसी 716 50 (2014) 11 एससीसी 355 121

बालविंदर सिंह (बिंदा) बनाम नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो [हिमा कोहली, जे.] 122 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

"100. तलाशी की अनुमति देने के लिए बंद स्थान के प्रभारी व्यक्ति -

(4). इस अध्याय के अंतर्गत तलाशी लेने से पहले, अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो इसे करने वाला है, उस इलाके के दो या दो से अधिक स्वतंत्र और सम्मानित निवासियों को बुलाएगा, जिसमें तलाशी की जाने वाली जगह स्थित है या किसी अन्य इलाके के निवासी, यदि उक्त इलाके का कोई ऐसा निवासी उपलब्ध नहीं है या खोज का गवाह बनने के लिए तैयार है, तो वह तलाशी में भाग लेने और देखने के लिए और उन्हें या उनमें से किसी को ऐसा करने के लिए लिखित रूप में आदेश जारी कर सकता है। "

25. उपरोक्त प्रावधान को नंगे पढ़ने से यह पता लगाया जा सकता है कि यह तलाशी से संबंधित एक सामान्य प्रावधान है और एक बंद स्थान पर लागू होता है, उदाहरण के लिए,

एक निवास, कार्यालय, दुकान, एक निर्मित परिसर आदि, जहां जांच द्वारा तलाशी की आवश्यकता होती है। यह इस संदर्भ में है कि धारा 100 दंड प्रक्रिया संहिता उप-धारा (4) में यह प्रावधान है कि प्रक्रिया की शुद्धता बनाए रखने के लिए, तलाशी लेने से पहले, उस इलाके के कुछ स्वतंत्र और सम्मानित निवासियों को, जहां तलाशी ली जानी है, तलाशी के गवाह के रूप में शामिल किया जाए।

26. इस मामले में, एन. सी. बी. के अधिकारियों द्वारा सेक्टर 24/25, चंडीगढ़ के गोल चक्कर के पास एक खुले क्षेत्र में नाका लगाया गया था। वह स्थान ऐसा था कि आसपास कोई निवासी नहीं था और नाका का समय 12 दिसंबर, 2005 को सुबह 01.00 का एक अलौकिक समय था। इस पृष्ठभूमि में, दो स्वतंत्र गवाह जो जालंधर से चंडीगढ़ की ओर गाड़ी चला रहे थे, उन्हें एन. सी. बी. के अधिकारियों ने फटकार लगाई और जाँच में शामिल हो गए। इसलिए, सोनू 8 की गवाही पर संदेह की छाया डालने की कोशिश की गई कि वह असली अपराधी था, स्पष्ट रूप से एक झूठी कहानी है जिसे कायम नहीं रखा जा सकता है। दूसरे स्वतंत्र गवाह मुकेश कुमार मुकर गए थे और अभियोजन पक्ष ने उनसे पूछताछ नहीं की थी। परिणामस्वरूप, बचाव पक्ष के दो गवाह, प्रकाश राम 31 और रविकांत पवार 32, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए-सतनाम सिंह 5, यह प्रदर्शित करने के लिए कि मुकेश कुमार एक वास्तविक गवाह था, शायद ही किसी सहायता के लिए होंगे। अपीलार्थी के विद्वान वकील-सतनाम सिंह 5 द्वारा इंगित की जाने वाली अन्य प्रक्रियात्मक विसंगतियों को प्रकृति में इतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है कि अपीलार्थी-सतनाम सिंह 5 के खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित पूरे मामले को अस्थिर या ध्वस्त कर दिया जाए।

(IV) निष्कर्ष

27. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि अपीलार्थी-सतनाम सिंह 5 बरी करने का मामला बनाने में विफल रहे हैं। इसलिए, दोषी ठहराए जाने के आदेश और सतनाम सिंह 5 पर लगाई गई सजा को बरकरार रखा गया है। तदनुसार 2014 की आपराधिक अपील सं. 1933 को खारिज कर दिया जाता है और निचली अदालत द्वारा सतनाम सिंह 5 पर लगाए गए दोषसिद्धि के आदेश और सजा को उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा जाता है। हालाँकि, 2014 की आपराधिक अपील No.1136 को अनुज्ञात गई है और अपीलार्थी, बलविंदर सिंह 3 को बरी कर दिया गया है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपीलों का निपटारा किया गया।

निधि जैन